RAJYA SABHA

Friday, the 22nd August, 2003/31 Sravana, 1925 (Saka)

The House met at eleven of the Clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*421. [The questioners (Dr. Abrar Ahmed) and Shrimati Ambika Soni) were absent. For answers *vide* page 31 *infra.*]

*422. [The questioners (Shri K. Natwar Singh and Dr. T. Subbarami Reddy) were absent. For answers *vide* page 32 *infra.*]

Literacy rate among muslim women

*423. SHRI SANJAY NIRUPAM : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the literacy rate among Muslim women is growing in India;

(b) if so, the details thereof, State-wise; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. SANJAY PASWAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) As per census 2001, the Female Literacy rate has increased by 14.8 percentage points. *i.e.* 39.3% in 1991 to 54.16% in 2001. According to the Registrar General of India, the data pertaining to the literacy rate among Muslim women as per 2001 Census is not available. However, as per the National Sample Survey Organization (NSSO) 55th Round 1999–2000, the Muslim female literacy rate of the country is 62.2% for Urban areas and 42.1% for Rural areas. Table indicating the State-wise Muslim female literacy rate (Rural and Urban) is enclosed.

485 RSS/2004—1

Table

Literacy Rate among Muslim Women as Per NSSO—55th Round Survey (July 1999-June 2000)

Sl.No.	State/UT	Muslim Female Literacy Rate	
		Rural Areas	Urban Areas
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	39.5	62
2.	Arunachal Pradesh	N.A.	N.A.
3.	Assam	51.1	74
4.	Bihar	25.5	51.9
5.	Goa	N.A.	72.6
6.	Gujarat	49.2	76
7.	Haryana	15.1	46.9
8.	Himachal Pradesh	46.6	74.9
9.	Jammu and Kashmir	39.8	59.9
10.	Karnataka	53.7	71.6
11.	Kerala	83	87.1
12.	Madhya Pradesh	40.8	64.9
13.	Maharashtra	55.9	73.7
14.	Manipur	34.3	72.9
15.	Meghalaya	89.1	N.A.
16.	Mizoram	N.A.	N.A.
17.	Nagaland	N.A.	N.A.
18.	Orissa	57.8	50.2
19.	Punjab	52.6	61.9
20.	Rajasthan	21.8	51
21.	Sikkim	N.A.	N.A.

1	2	3	4
22.	Tamil Nadu	76.4	74.7
23.	Tripura	55.9	69.9
24.	Uttar Pradesh	26.8	44.9
25.	West Bengal	46.5	56.5
26.	A and N Islands	84.1	87.3
27.	Chandigarh	N.A.	75.6
28.	D and N Haveli	N.A.	N.A.
29.	Daman and Diu	N.A.	94.4
30.	Delhi	N.A.	57.2
31.	Lakshadweep	82.8	82.7
32.	Pondicherry	N.A.	84.2
	All India	42.1	62.2

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय यह सही है कि इस देश में महिलाओं की साक्षरता बढ़ रही है। जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 14.8 प्रतिशत की जो वृद्धि दर है, वह पिछले दस सालों में रिकार्ड की गयी है। लेकिन इसके साथ साथ यह जो निष्कर्ष निकाला गया है, पता नहीं किस तरह के फिगर्स, किस तरह के आंकड़ों के जरिए, कि मुस्लिम महिलाओं में भी साक्षरता की दर तेजी से बढ़ रही है–यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बीच में, हाल के वर्षों में यूएनडीपी की तरफ से जो फाइंडिंग आयी है उसमें यूएनडीपी का कहना यह है कि हिन्दुस्तान में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, बहुत स्लो है। इसके अतिरिक्त डा॰ जोया हसन करके जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, पता नहीं मंत्री महोदय को उनके बारे में मालूम है या नहीं, उन्होंने हाल मे जेएनयू के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी कि मुस्लिम महिलाओं के बीच साक्षरता का क्या प्रतिशत है। उनकी जो फाइंडिंग है, वह बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत धक्का देने वाली है। उनके अनुसार उत्तर भारत में सिर्फ 15 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं साक्षर हैं, उनको ऐजुकेशन मिल पायी है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में सिर्फ तीन प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं ऐसी है जो कालेज जाती हैं। क्या डा॰ जोया हसन के इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की जानकारी सरकार को है?

डा॰ संजय पासवान: आदरणीय सभापति महोदय मुस्लिम हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो–ऐसी महिलाओं का साक्षरता का रेट कम है। कुल मिलाकर सबसे अधिक रेट किस समाज में है, यह कहना मुश्किल है। किन्तु आज देश के 45 जिले ऐसे हैं जिनमें फीमेल लिट्रेसी सबसे कम है। उसमें अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम्स की संख्या तीस परसेंट के आस-पास है। इसलिए उन 45 जिलों के लिए, उसमें विशेषकर बिहार, उड़ीसा उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के जिले हैं, कई प्रयास चलाए जा रहे हैं। जहां तक दो रिपोर्ट्स का माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, यूएनडीपी का और डा॰ जोया हसन की रिपोर्ट का, वह सरकार के संज्ञान में अभी नहीं आया है। हमारी जो आधिकारिक रिपोर्ट्स हैं, वे आनी बाकी हैं। हम सब लोग इस संबंध में प्रतिबद्ध हैं कि मुस्लिम महिलाओं में तथा बाकी अन्य महिलाओं में साक्षरता की दर कैसे बढ़े। 1981 के बाद से साइजेबल ग्रोथ दिखाई पड़ी है इसलिए स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। और भी आगे कई प्रयास हम लोगों की तरफ से होने वाले हैं जिनसे तमाम महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़े। ये प्रयास हम जारी रखेंगे।

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, पता नहीं मैं इसे संतोषजनक स्थिति कैसे मानूं? बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर है, वह 25 प्रतिशत है—जहां से स्वयं मंत्री जी आते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत 26 प्रतिशत है। इसको कैसे संतोषजनक माना जाए, समझ में नहीं आता। आम तौर पर महिलाओं के बीच साक्षरता बढ़ाने के लिए हमारे देश में एक अभियान चल रहा है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, जिसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। यह एक बहुत ही जरूरी अभियान है। लेकिन आम महिलाओं की तुलना में इस देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की मुस्लिम महिलाएं एक अलग जीवन जीती हैं, बिल्कुल अलग परिस्थितियों में जीती हैं। उस हिसाब से मुस्लिम महिलाओं के बीच साक्षरता तेजी से बढ़ाने के लिए मुस्लिम महिलाओं के जीवन को और सुरक्षा देने के लिए एक विशेष तौर का प्रोग्राम चलाया जाना जरूरी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मुस्लिम महिलाओं के बीच सुधार का कार्यक्रम चलाने के दृष्टिकोण से साक्षरता का कोई विशेष कार्यक्रम बनाने का विचार कर रही है?

मानव संसाधान विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर सारे सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को बड़ी गंभीरता से ध्यान देना है। हम लोगों ने इस बारे में गहन अध्ययन भी किया है और यह पाया है कि हमारे देश में अधिकांश महिलाओं की जो साक्षरता दर में कमी है उसमें मुस्लिम महिलाएं और परिगणित जाति की महिलाएं काफी पीछे हैं। सबसे पहले इस बात का अध्ययन किया गया है कि वे कौन से जिले हैं जिनमें मुस्लिम जनसंख्या काफी बड़ी मात्रा में है, तीस प्रतिशत या उसके आस-पास है। व

पर किन ब्लाक्स में, किन स्थानों पर यह कठिनाई सबसे ज्यादा है और आज वहां पर जो हमारा सर्वशिक्षा अभियान का कार्यक्रम है उसमें हमने अभी विशेष रूप से इस बात का आयोजन किया है और इसी के संबंध में आगे एक प्रश्न और भी है जिसकी हम चर्चा करेंगे। उसमें यह व्यवस्था की गई है कि उन स्थानों पर जहां भी गावों में आज आवश्यकता है, उन बच्चियों के लिए विद्यालय खोलने के लिए, वहां वे खोले जाएं। हम यह भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उस गांव में ही खोल दिए जाएं जहां ये जाति रहती हैं और उस जाति की ही अध्यापिकाएं नियुक्त की जाएं। क्योंकि यह देखने में आया है कि अगर अध्यापिका वहां की होती है और केवल बालिकाओं का विद्यालय होता है तब बालिकाएं विद्यालय में ज्यादा आती हैं; इस दृष्टि से हम यह प्रयास कर रहे हैं कि वहां बालिकाओं के स्कूल खुलें जो केवल बालिकाओं के हों और यथा संभव उसमें उसी गांव के आस-पास की प्रशिक्षित, उसी जाति की महिला अध्यापिका नियुक्त की जाएं। उससे यह कार्यक्रम अधिक बल पकड़ेगा और साक्षरता की दर आगे बढ़ेगी साथ ही साथ हम मदरसों के लिए भी यह कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी शिक्षा के लिए प्रयत्न किए जाएं क्योंकि बहुत सी मुस्लिम लड़कियां मदरसों में जाती हैं तो वहां पर हम उनको साक्षरता से और अधिक विषय पढ़ाने की दृष्टि से भी हम उनकी मदद कर रहे हैं। यह एक सघन प्रयास है ताकि वे आगे बढ़ें। जब वे नीचे से आगे बढ़ेंगी तो फिर कालेज में भी आगे आएंगी, यह उसका परिणाम होगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें मुस्लिम समुदाय को आगे आना पड़ेगा कि वे अपनी बच्चियों को विद्यालयों में पढ़ने के लिए आगे भेजें। आज से पचास-साठ साल पहले जिनको हम को-एड्स कहते हैं या मिले जुले विद्यालय कहते हैं, हिन्दू बच्चियां भी उनमें ली जाती थीं। लेकिन जैसे धीरे-धीरे वहां शिक्षा का प्रयास हुआ, आज बच्चियां हर प्रकार के विद्यालय में और सह शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं। जैसे-जैसे नीचे से शिक्षा बढ़ेगी, मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले पांच सालों में इस समस्या का हम निवारण कर देंगे और अधिकांश मुस्लिम बच्चियां पढ़ेंगी और आगे भी विद्यालयों में आएंगी।

SHRI. P.G. NARAYANAN: Mr. Chairman, Sir, I want to know from the hon. Minister about the performance of the Southern States in literacy. How does it compare with the Northern States?

DR. MURLI MAHNOHAR JOSHI: There are districts both in the Northern and in Southern States. We have identified those districts, and I can give you a list of those districts. It is true that most of these districts are in the Northern part, because there is a general gap in education in States like Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal. There is a general deficiency in overall education. Therefore, these are the States where we have a larger gap, both between the female literacy and male literacy, as well as, between Muslims and non-Muslims.

श्री ईसाम सिंह: सभापति महोदय, उत्तर में ग्रामीण क्षेत्र के 11 राज्यों में साक्षर रिकार्ड के बारे में यह कहा गया है कि यह उपलब्ध नहीं है और 6 राज्य शहरी हैं। पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिकार्ड कब तक उपलब्ध हो जाएगा? दूसरे यह कि आठ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम साक्षर, जो इसमें दिखाया गया है और 9 राज्य शहरी क्षेत्र में दिखाए गए हैं तो महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समुदाय की महिलाओं में साक्षरता बढ़े इस संबंध में वजीफे से संबंधित सम्पूर्ण भारत में, क्या सरकार कोई विशेष प्रस्ताव रखना चाहती है या रखेगी?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदय वैसे मैंने अभी उत्तर दिया था, लेकिन अब उसी को मैं फिर दोहरा देता हूं कि हमने यह व्यवस्था की है कि जिन गांवों में इन जातियों की ज्यादा बालिकाएं रहती हैं और वे अशिक्षित हैं, वहां उन गांवों में भी स्कूल खोल दिए जाएं। सर्वशिक्षा अभियान के तहत हमने यह योजना बना दी है और यह भी है कि वहां उन्हीं जातियों की अध्यापिकाओं की नियुक्ति कर दी जाए ताकि बच्चियों को पढ़ने में सुविधा और सरलता मिले और जो सामाजिक एक मान्यता है, उसके आधार पर भी वे बच्चियों को स्कूल में भेज सकें। इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत सारी शिक्षा मुफ्त है, उसमें उनको पाठ्य पुस्तकें भी मुफ्त मिलती हैं। ऐसी उसमें व्यवस्थाएं भी हैं और बहुत कुछ उसके अंदर सुविधाएं उनको दी जाती हैं। यहां वजीफे का उतना सवाल नहीं उठता। इसके आगे भी हमने व्यवस्था की है कि जब वे सैकेंडरी क्षेत्र में जाएं तब भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं उनके लिए रहें। जब यहां से संख्या बढ़ेगी तो फिर वे विश्वविद्यालयों में भी जायेंगी, तो उसके लिए भी एक अलग स्कीम हमने बनाई है जिसमें ग्रेजुएशन तक, बी॰ए॰ तक, हम सभी लड़कियों के लिए शिक्षा की सुविधा देने जा रहे हैं, खास तौर पर जो गरीब हैं, उसकी स्कीम भी हमारे पास विचाराधीन है कि किस प्रकार से उसको लागू किया जाए, जिससे कि उच्च शिक्षा में भी इन वर्गों और इन जातियों की बच्चियों को सुविधा मिल सके। अभी जो व्यवस्था है उसमें खास तौर पर जो शैडयूल्ड ट्राइब्ज और शैडयूल्ड कास्ट्स की लड़कियां होंगी उनके लिए हमारा प्रस्ताव यह भी हो रहा है कि उन्हें अगर ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: जोशी जी, आगे क्वश्चन और है, उसके लिए जवाब रिज़र्व रखिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: इनको मैं पूरा जवाब दे दूं ताकि आगे का क्वश्चन भी खत्म हो जाए।

SHRI DINESH TRIVEDI: Mr. Chairman, Sir, first of all, I would like to compliment the hon. Minister for taking care of all people from all segments of the society. It is really encouraging that the female literacy rate has really increased by 14.8 per cent. I would also like to compliment the hon. Minister that Kendriya Vidyalaya's results this year have been extraordinarily outstanding. Sir my question is on two aspects. One

when we talk about the children, whether it is Muslim or downtrodden, children are taken as a source of income. This may not be directly related to hon. Minister's Ministry, but I would like to know if there is something being done. Children are used to go out for earning. That is one aspect. The other aspect is, in order to give opportunity to Muslim women or downtrodden, you do require teachers. Sir, I would like to know whether there are any schemes to train the teachers, especially to teach this class of our society.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, जहां तक इस बात का सवाल है कि जिन बच्चों को पढ़ने के लिए अध्यापकों और अध्यापिकाओं की आवश्यकता है, मूलत: शिक्षक प्रशिक्षण का काम राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन हमारी कोशिश भी रहती है और हम उनको बार-बार बताते भी रहते हैं कि इस प्रकार की आवश्यकता है, आप इस काम को करें। हम बार-बार इसका आग्रह करते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह काम राज्य सरकारों के अधीन होने की वजह से उसकी प्रगति की दर पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन इस बात में वजन है और हम इसको स्वीकार करते हैं कि इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की वृद्धि होनी चाहिए और हम राज्य सरकारों को फिर से लिखेंगे कि इस तरफ वे पूरा ध्यान दें।

*424. [The questioners (Shri Kapil Sibal and Shri Ram Jethmalani) were absent. For answers *vide* page 33-34 *infra*.]

National Programme for Education of Girls

*425. SHRIMATI SHABANA AZMI :†

DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have cleared the ambitious National Programme for Education of Girls at the elementary level;

(b) if so, the details of the programme;

(c) what is the total amount set for this purpose;

(d) by what time the programme is likely to be implemented; and

(e) the States where this programme is likely to be introduced?

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Shabana Azmi